



# राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, मंगलवार, 17 अक्तूबर, 2006/25 आश्विन, 1928

हिमाचल प्रदेश सरकार

शहरी विकास विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 10 अक्तूबर, 2006

संख्या एल० एस० जी०-ए (3)-1/71-11.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, तारीख 7 जून, 1988 के राजपत्र (असाधारण) हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना तारीख 26-5-1988 के अधिक्रमण में तथा हिमाचल प्रदेश नगरीय किराया नियन्त्रण अधिनियम, 1987 (1987 का 25) की धारा 24 की उप-धारा (1) के द्वारा उनमें निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, समस्त जिला एवं सत्र न्यायाधीशों/अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीशों को, उनकी अपनी-अपनी अधिकारिता के नगरीय क्षेत्रों की बाबत, में, कथित अधिनियम की धाराओं 4, 5, 11, 12, 13, 14 [14(3) (क) (iii) के सिवाए] और 21 के अन्तर्गत किराया नियन्त्रक द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई हेतु अपीली प्राधिकारियों की शक्तियां प्रदान करते हैं।

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/-  
प्रधान सचिव (शहरी विकास)।

[Authoritative English Text of Notification No. LSG-A (3)-1/71-II, dated 10th October, 2006 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].

## NOTIFICATION

*Shimla-2, the 10th October, 2006*

**No. LSG-A(3)-1/71-II.**—In supersession of this Department notification of even number dated 26-5-1988, published in Rajpatra, Himachal Pradesh (extra-ordinary), dated 7th June, 1988 and in exercise of the powers vested in him under sub-section (1) of Section 24 of the Himachal Pradesh Urban Rent Control Act, 1987 (Act No. 25 of 1987) the Governor, Himachal Pradesh is pleased to confer the powers of appellate authorities on all the District and Sessions Judges/Additional District and Sessions Judges in respect of the urban areas in their respective existing jurisdictions to hear appeals against the orders made by the Rent Controllers under sections 4, 5, 11, 12, 13, 14 [except 14(3) (a)(iii)] and 21 of the said Act.

By order,

Secretary (UD).